After studying this chapter, the learners will understand

- the concepts of Human Resource, Human Capital Formation and Human Development
- the links between investment in human capital, economic growth and human development
- the need for government spending on education and health
- the state of India's educational attainment.

इस अध्याय को पढ़न के बाद आप

- मानव संसाधन, मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे;
- मानव पूँजी में निवेश, आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता को समझ पाएँगे और
- भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

INTRODUCTION

Think of one factor that has made a great difference in the evolution of mankind. Perhaps it is man's capacity to store and transmit knowledge which he has been doing through conversation, through songs and through elaborate lectures. But man soon found out that we need a good deal of training and skill to do things efficiently. We know that the labour skill of an educated person is more than that of an uneducated person and hence the former is able to generate more income than the latter and his contribution to economic growth is, consequently, more.

परिचय

मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान-संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएँ ही हैं, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े-बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करता आ रहा है। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम-कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से पहला, दूसरे की अपेक्षा, अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है।

Education is sought not only as it confers higher earning capacity on people but also for its other highly valued benefits: it gives one a better social standing and pride; it enables one to make better choices in life; it provides knowledge to understand the changes taking place in society; it also stimulates innovations.

शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है. व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढावा देता है।

WHAT IS HUMAN CAPITAL? मानव प्रॅंजी क्या है?

resources like land into physical संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूँजी में capital like factories, similarly, it can परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने also turn human resources like छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, nurses, farmers, teachers, students अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव into human capital like engineers and पूँजी में भी परिवर्तित कर सकता है। समाज को doctors. Societies need sufficient human capital in the first place-in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals. In other words, we need good human capital to produce पूँजी जैसे - नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, other human capital (say, nurses, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए farmers, engineers...). This means that we पूँजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है need investment in human capital to कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूँजी के रूप produce more human capital out of में परिवर्तित करने के लिए मानव पूँजी निवेश human resources.

Just as a country can turn physical जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूँजी की ज़रूरत है, जो एसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफ़ेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव teachers, doctors, शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव करने की भी आवश्यकता है।

- (i) What are the sources of human capital?
- (ii) Is there any relation between human capital and economic growth of a country?
- (iii) Is the formation of human capital linked to man's all-round development or, as it is now called, human development?
- (iv)What role can the government play in human capital formation in India?

- (क) मानव पूँजी के स्रोत क्या हैं?
- (ख) क्या किसी देश की आर्थिक संवृद्धि और वहां की मानव पूँजी में कोई संबंध होता है?
- (ग) क्या मानव पूँजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सवांगीण विकास से है जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है?
- (घ) भारत में मानव पूँजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है?

SOURCES OF HUMAN CAPITAL

Investment in education is considered as one of the main sources of human capital. There are several other sources as well. Investments in health, on- thejob training, migration and information are the other sources of human capital formation.

Why do your parents spend money on education? Spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by companies with the objective of increasing future profits over a period of time.

मानव पूँजी के स्रोत

शिक्षा में निवेश को मानव पूँजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूँजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं।

आपके माता-पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियां निश्चित अविध में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर करती हैं।

Like education, health is also considered as an important input for the development of a nation as much as it is important for the development of an individual.

A sick labourer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. Hence, expenditure on health is an important source of human capital formation.

शिक्षा की भाँति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा। इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूँजी के

निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

Preventive medicine (vaccination), curative medicine (medical intervention during illness), social medicine (spread of health literacy) and provision of clean drinking water and good sanitation are the various forms of health expenditures. Health expenditure directly increases the supply of healthy labour force and is, thus, a source of human capital formation.

प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (टीकाकरण), चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा) तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार) और इनके साथ-साथ स्वच्छ पेय जल का प्रावधान आदि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव प्रँजी निर्माण का एक स्रोत है।

People migrate in search of jobs that fetch them higher salaries than what they may get in their native places. Unemployment is the reason for the rural-urban migration India. Technically qualified persons, like engineers and doctors, migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries. Migration in both these cases involves cost of transport, higher cost of living in the migrated places and psychic costs of living in a strange sociocultural setup. The enhanced earnings in the new place outweigh the costs of migration; hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation.

व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन/पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन मुख्यत: गाँवों में बेराजगारी के कारण ही होता है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता. डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवसनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं। किंतु नये स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अत: प्रवसन पर व्यय भी मानवीय पूँजी निर्माण का स्रोत है।

People spend to acquire information relating to the labour market and other markets like education and health. For example, people want to know the level of salaries associated with various types of jobs, whether the educational institutions provide the right type of employable skills and at what cost. This information is make decisions to necessary regarding investments in human capital as well as for efficient utilisation of the acquired human capital stock. Expenditure incurred for acquiring information relating to the labour market and other markets is also a source of human capital formation.

व्यक्ति श्रम बाज़ार तथा दूसरे बाज़ार जैसे. शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं. कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या हैं या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएँ सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर? यह जानकारी मानव पूँजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूँजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

The concept of physical capital is the base for conceptualising human capital.

भौतिक पूँजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूँजी के वैचारिक आधार की रचना की गयी है।

Physical and Human Capital

Both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decisions. Decision regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard. The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investments and then rationally decides which one of the investments should be made. The ownership of physical capital is the outcome of the conscious decision of the owner — the physical capital formation is mainly an economic and technical process. A substantial part of the human capital formation takes place in one's life when she/he is unable to decide whether it would maximise her/his earnings. Children are given different types of school education and health care facilities by their parents and the society. The peers, educators and society influence the decisions regarding human capital investments even at the tertiary level, that is, at the college level. Moreover, the human capital formation at this stage is dependent upon the already formed human capital at the school level. Human capital formation is partly a social process and partly a conscious decision of the possessor of the human capital.

भौतिक और मानव पूँजी दोनों ही प्रकार का पूँजी सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। भौतिक पूँजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। इन गणनाओं के बाद ही वह अपना विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूँजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है-भौतिक पूँजी निर्माण मुख्यत: एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूँजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है, जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पायेगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज उच्चतर स्तरों (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) पर मानव पूँजी में निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। फिर भी इस स्तर पर मानव पूँजी निर्माण, विद्यालय स्तर पर मानव पूँजी निर्माण, पर निर्भर करता है। मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशत: मानव पूँजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है।

Physical capital is tangible and can be easily sold in the market like any other commodity. Human capital is intangible; it is endogenously built in the body and mind of its owner. Human capital is not sold in the market; only the services of the human capital are sold and, hence, there arises the necessity of the owner of the human capital to be present in the place of production. The physical capital is separable from its owner, whereas, human capital is inseparable from its owner.

भौतिक पूँजी किसी भी अन्य वस्तु की भाँति दुश्य होती है। उसे किसी भी वस्तु की तरह बाज़ार में बेचा जा सकता है। मानव पूँजी अदश्य होती है-यह धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची-बसी होती है। बाजार में मानव पूँजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है इसलिए मानव पूँजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। भौतिक पूँजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, किंतु मानव पूँजी का स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता।

The two forms of capital differ in दोनों प्रकार की पूँ जियों में उनके terms of mobility across space. स्थानों की गतिशिलता के आधार पर Physical capital is completely अंतर होता है। प्राय: कुछ कृत्रिम mobile between countries except for some artificial trade restrictions. Human capital is not विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता perfectly mobile between रहता है। किंतु मानव प्रँजी का प्रवाह countries as movement is इतना निर्बाध नहीं होता, इसके मार्ग में restricted by nationality and राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊँची बाधाएँ culture. Therefore, physical capital formation can be built even through imports, whereas human capital formation is to be जाता है, किंतु मानवीय पूँजी की रचना done through conscious policy तो समाज तथा अर्थव्यवस्था की अंतर्भृत formulations in consonance with विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति the nature of the society and निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा सरकार economy and expenditure by the और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर state and the individuals.

होती है।

Human capital benefits not only the owner but also the society in general. This is called external benefit. An educated person can effectively take part in a democratic process and contribute to the socio-economic progress of a nation. A healthy person, by maintaining personal hygiene and sanitation, stops the spread of contagious diseases and epidemics. Human capital creates both private and social benefits, whereas physical capital creates only private benefit. That is, benefits from a capital good flow to those who pay the price for the product and services produced by it.

मानव पूँजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरन् सारा समाज लाभांवित होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट की सामाजिक, आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्तर पर तथा आस-पास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोक उन्हें महामारियों का रूप धारण नहीं करने देता। मानवीय पूँजी से व्यक्तिगत के साथ-साथ सामाजिक हितलाभों का भी सृजन होता है। किंतु भौतिक पूँजी तो प्राय: निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है। पूँजीगत पदाथों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका सकें।

Human Capital and Economic Growth: Who contributes more to national income - a worker in a factory or a software professional? We know that the labour skill of an educated person is more than that of an uneducated person and that the former generates more income than the latter. Economic growth means the increase in real national income of a country; naturally, the contribution of the educated person to economic growth is more than that of an illiterate person.

मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या 'सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ' का? हम जानते ही हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा।

This enhanced productivity of human beings or human capital contributes substantially not only towards increasing labour productivity but also stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies. Education provides knowledge to understand changes in society and scientific advancements, thus, facilitate inventions and innovations. Similarly, the availability of educated labour force facilitates adaptation to new technologies.

मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव प्रँजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि यह साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात् करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है- जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है।

of schooling, teacher-pupil ratio and अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार enrolment rates may not reflect the qt शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को quality of education; health services measured in monetary terms, life expectancy and mortality rates may not प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय. reflect the true health status of the जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश people in a country. Using the indicators की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर mentioned above, an analysis of का सही ज्ञान नहीं होता। यदि इन सूचकों improvement in education and health का सहा ज्ञान नहा होता। याद इन सूचका का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील sectors and growth in real per capita in both developing and देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और developed countries shows that there is प्रतिव्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें convergence in the measures of human तो हमें मानव पूँजी के परिवर्तनों में capital but no sign of convergence of per capital real income. In other words, the human capital growth in developing त्रांतिक आय में एसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट countries has been faster but the नहीं होती। दूसरे शब्दों में, विकासशील growth of per capita real income has देशों में मानव पूँजी की संवृद्धि तो बहुत not been that fast.

education measured in terms of years स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक-शिक्षार्थी तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है।

India recognised the importance of human capital in economic growth long ago. The Seventh Five Year Plan says, "Human resources development (read human capital) has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population. Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired directions."

भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक संवृद्धि में मानव पूँजी के महत्व को समझ लिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है- "एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों (मानव पूँजी) के विकास को आर्थिक विकास की यक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पा कर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ान वाली परिसंपत्ति बन जायेगी। साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी।"

knowledge resources. We have not looked ahead into the implications of being the world's third largest economy. It will be a totally different environment. think **Ecosystems** force to **US** differently, and achieving this milestone will have ramifications all across the country. Are we ready to take our place besides the USA and China as the top three largest economies of the world and be confident of sustaining it in the following years? To do this, we will need a knowledge society based on a robust education system, with all the requisite attributes and characteristics in the context of changes in knowledge demands, technologies, and the way in which society livesand works."

Our ten trillion economy will not be भारत अब छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम driven by natural resources, but by पाँच-सात वर्षों में पाँच ट्रिलियन तक पहुँच जाएँगे। जोकि भारत को विश्वस्तर पर चौथे या पाँचवे स्थान ले जायगा। अभी तक हमने भारत को विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उसके निहितार्थी पर गौर नहीं किया है। यह एक बदलते परिवेश का पूर्णत: नया अनुभव होगा। इस प्रकार से एसे पारिस्थितिक तंत्र, हम सभी को विभिन्न दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति की सम्भावनाओं का फैलाव समस्त देश में हो सके। क्या हम अपने भारत देश को इस आत्मविश्वास के साथ अमेरिका और चीन के समक्ष विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुँचा सकते हैं और आगामी वर्षों में इस स्थान को बनाय रखनेमें सक्षम हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मज्बूत शिक्षा प्रणाली पर आधारित ज्ञानवधंक समाज का गठन हो, जिसमें ज्ञान की मागों, प्रौद्योगिकीय और समाज के काम करने के तरीकों में बदलाव के तत्वों का समावेश हो। इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूँजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है।

India as a Knowledge Economy

The Indian software industry has been showing an impressive record decades. the two past over Entrepreneurs, bureaucrats politicians are now advancing views about how India can transform itself into a knowledge-based economy by using information technology (IT). There have been some instances of villagers using e-mail which are cited as examples of such transformation. Likewise, e-governance is being projected as the way of the future. The value of IT depends greatly on existing of economic the level development. Do you think IT based services in rural areas will lead to human development?

ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत भारत में पिछले दो दशकों से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आपको ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ई-मेल (म.डंपस) के प्रयोग के उदाहरणों को एसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। इसी प्रकार से ई-प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यमान तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना, प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएँ मानव विकास करने में सक्षम होंगी?

HUMAN CAPITAL AND HUMAN DEVELOPMENT

is a clear distinction between them. Human capital considers education and health as to increase labour productivity. Human development on the idea that based education and health are integral to human well-being because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value. Human capital treats human beings as a means to an end; the end being the increase in productivity.

मानव पूँजी और मानव विकास

ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते-जुलते भले ही The two terms sound similar but प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूँजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने -लिखनतथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह एसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूँजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है, अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो।

Human welfare should be increased through investments in education and health even if such investments do not result in higher labour productivity. Therefore, basic education and basic health are important in themselves, irrespective of their contribution to labour productivity.

भले ही शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य स्विधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है।

STATE OF HUMAN CAPITAL FORMATION IN INDIA

In this section we are going to analyse human capital formation in India. We have already learnt that human capital formation is पूँजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य the outcome of investments in education, health, on-the-job sources of human capital formation. We know that India is a federal country with a union संघीय है जिसमें केंद्र, राज्य तथा government, state governments स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर and local (Municipal Municipalities and Village Panchayats).

भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति इस खंड में हम भारत में मानव पूँजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ चुके हैं कि मानव स्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना training, migration and निवेश का परिणाम है। इनमें से शिक्षा information. Of these education और स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माण के दो and health are very important सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था governments पालिका, ग्राम पंचायत आदि) हैं। Corporations,

The Constitution of India mentions the functions to be carried out by each level of government. Accordingly, expenditures on both education and health are to be carried out simultaneously by all the three tiers of the government. Analysis of health sector is taken up in Chapter 8; hence, we will analyse only the education sector here.

भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कायों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ-साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है। अत: यहां हम केवल शिक्षा क्षेत्रक का विश्लेषण करेंगे।

analysis of the education sector in India, we will look into the need for government intervention in education and health sectors. We do understand that education and health care services create both private and social benefits and this is the reason for the existence of both private and public institutions in the education and health service markets. **Expenditures on education** and health make substantial long-term impact and they cannot be easily reversed; hence, government intervention is essential

हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाज़ार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है।

admitted to a school or health care centre where the required services are not provided, before the decision damage would have been done. Moreover, individual consumers of these services do not have complete services and their costs. In this situation, the providers of education services acquire health and monopoly power and are involved in exploitation. The role of government in this situation is to ensure that the private providers of these services adhere to the standards stipulated by the government and charge the correct price.

instance, once a child is मान लीजिए, जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है, जहां आवश्यक सुविधाएँ is taken to shift the child to another नहीं प्रदान की जा रही हों तो इससे पहले कि institution, substantial amount of बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं information about the quality of के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रही संस्थाएँ एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यहां सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएँ देने तथा उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करे।

level, departments of education **University Grants Commission** (UGC) and All India Council of परिषद आती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्रक के facilitate institutions which come under the education sector. Similarly, the ministries of health at the union and state level, departments of health and various **National** like organisations **Medical Commission and Indian** Council for Medical Research (ICMR) facilitate institutions which come under the health sector.

India, the ministries of भारत में शिक्षा क्षेत्रक के अंतर्गत संघ education at the union and state और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा and various organisations like राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण National Council of Educational परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग Research and Training (NCERT), और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा Technical Education (AICTE) अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही हैं।

considered as a right of the citizens and those from the stepping up expenditures in the education sector over the years and considerably increase the average educational attainment of Indians.

Furthermore, when basic यही नहीं भारत की अधिकांश जनता अति education and health care is विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च citizens, then it is essential that शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब the government should provide बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल education and health services सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान free of cost for the deserving िलया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि socially oppressed classes. सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर Both, the union and state सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वगों को, governments, have been सरकार ये सुविधाएँ नि:शुल्क प्रदान करे। शत-प्रतिशत साक्षरता और भारतीयों की in order to fulfil the objective of औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए attaining cent per cent literacy केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वषों से अपने शिक्षा क्षेत्रक पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं।

government is expressed in two ways (i) as a percentage of 'total percentage of Gross Domestic 'education expenditure of GDP' development of education in the country.

EDUCATION SECTOR IN INDIA शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि Growth in Government Expenditure on Education: Do you know how much the government spends on कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए education? This expenditure by the गये शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस government expenditure' (ii) as a व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे -Product (GDP). The percentage of (क)कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत 'education expenditure of total तथा (ख) सकल घरेलू उत्पाद में इसका government expenditure' indicates प्रतिशत। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर the importance of education in the scheme of things before the व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में government. The percentage of शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल expresses how much of people's घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत income is being committed tothe यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

During 1952-2014, education expenditure as percentage of total government expenditure increased from 7.92 to 15.7 and as percentage of GDP increased from 0.64 to 4.13. Throughout this period the increase in education expenditure has not been uniform and there has been irregular rise and fall.

1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92 प्रतिशत से बढ़कर र 15.7 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13 प्रतिशत हो गया है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है इसमें अनियमित रूप से उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

major share of total education expenditure and the share of higher/tertiary education (institutions of higher learning universities) is the least. Though, on an average, the education is higher than that of that financial resources should इसका, अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय education education.

Elementary education takes a कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर/तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं (उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे- महाविद्यालयों. like colleges, polytechnics and बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि) पर होने वाला व्यय सबसे कम है। government spends less on यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर tertiary education, 'expenditure शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतू per student' in tertiary प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय elementary. This does not mean प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। be transferred from tertiary संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक to elementary शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए।

In 2014-15, the per capita public expenditure on elementary education differs considerably across states from as high as Rs 34,651 in Himachal Pradesh to as low as Rs 4088 in Bihar. This leads to differences in educational opportunities and attainments across states.

वर्ष 2014-15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफी अंतर है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च-स्तर 34,651 रु०. वहीं बिहार में यह मात्र 4,088 रु० है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है।

commissions. About 55 years ago, per cent of GDP be spent on education so as to make noticeable rate of growth in 1999, estimated India expenditure of around Rs 1.37 lakh crore over 10 years (1998-99 to 2006-07) to bring all Indian children in the age group of 6-14 years under the purview of school education.

One can understand the inadequacy विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के of the expenditure on education if aiछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की we compare it with the desired level education expenditure as तुलना की जाय तो इसकी अपर्याप्तता recommended by the various समझ में आ सकती है। 55 वर्ष पूर्व the Education Commission (1964– (1964–66) नियुक्त शिक्षा आयोग ने 66) had recommended that at least 6 सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों व की संवृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने in के लिए सकल घरेलू उत्पाद का educational achievements. The Tapas Majumdar Committee, कम-से-कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च appointed by the Government of किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

cent of GDP, the current level of a little over 4 per cent has of all children in the age group of 6-14 years.

Compared to this desired 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस level of education मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था expenditure of around 6 per कि देश के 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में been quite inadequate. In शामिल करने के लिए (1998-99 से principle, a goal of 6 per cent 2000-07) के दस वर्षों की अवधि में needs to be reached—this लगभग 1.3 लाख करोड रु. व्यय करना has been accepted as a must होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत for the coming years. In 2009, के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4 enacted the Right of Children प्रतिशत व्यय का स्तर बहुत कम है। आने to Free and Compulsory वाले वर्षों में 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक Education Act to make free पहुँचने की आवश्यकता है, जैसा कि education a fundamental right सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है।

Government of India has also started levying a 2 per cent 'education cess' on all Union taxes. The revenues from education cess has been earmarked for spending on elementary education. In addition to this, the government sanctions a large outlay for the promotion of higher education and new loan schemes for students to pursue higher education.

भारत सरकार ने सभी केंन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत "शिक्षा उपकार" लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकार से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धन राशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नयी ऋण योजना की भी घोषणा की गयी है।

Educational
Achievements in India:
Generally, educational
achievements in a
country are indicated in
terms of adult literacy
level, primary education
completion rate and
youth literacy rate.

भारत में शैक्षिक उपलब्धियां सामान्यतया किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है।

FUTURE PROSPECTS

Education for All — Still a Distant **Dream: Though literacy rates for** number of illiterates in India is as passed by the Constituent Assembly, **Principles of the Constitution that** the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the Constitution. Had we achieved this, we would have cent per cent literacy by now.

भविष्य की संभावनाएँ

सब के लिए शिक्षा – अभी भी एक both – adults as well as youth – सपना है। यद्यपि वयस्क और य्वा साक्षरता have increased, still the absolute दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी much as India's population was at देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है the time of independence. In 1950, जितनी स्वाधीनता के समय भारत की when the Constitution of India was जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने it was noted in the Directive 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के दस साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चोंके लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक शत-प्रतिशत साक्षरता हो गई होती।

Gender Equity — Better than Before:

The differences in literacy rates between males and females are narrowing signifying a positive development in gender equity; still the need to promote education for women in India is imminent for various reasons such as improving economic independence and social status of women and also because women education makes a favourable impact on fertility rate and health care of women and children. लिंग समता-पहले से बेहतर: अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है जो लिंग-समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं। जैसे. शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार और साथ ही स्त्री शिक्षा, प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है।

education pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level. Moreover, the level of unemployment among educated youth is the highest. As per NSSO data, in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural per cent Their urban areas was counterparts had relatively less level of unemployment at 16 per cent. The most severely affected ones were young rural female graduates as nearly 30 per cent of them are unemployed. In contrast to this, only about 3-6 per cent of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. The situation is yet to improve as indicated by the Periodic Labour Force Survey 2017-18. Therefore, the government should increase allocation for higher education and also improve the standard of higher education institutions, so that students are imparted employable skills in such institutions.

Higher Education — a Few Takers: The Indian उच्च शिक्षा—लेने वालों की कमी: भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हो युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत थी। उनके शहरी समकक्षों में 16 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30 प्रतिशत बेरोजगार हैं जो युवा ग्रामीण महिला थीं। इसके विपरीत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित य्वाओं में से केवल 3-6 प्रतिशत बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। अत: सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आबंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहां पढ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें

CONCLUSION

of human capital formation and human outlays for development education and health sectors. The spread of education and health services across different sectors of society should be ensured so as to simultaneously attain economic growth and equity. India has a rich stock of scientific and technical manpower in the world. The need of the hour is to better it qualitatively and provide such conditions so that they are utilised in India.

निष्कर्ष

The economic and social benefits मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास के development are well known. The union and state हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा governments in India have been तथा स्वास्थ्य क्षेत्रकों के विकास के लिए earmarking substantial financial पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ करायी जानी चाहिए, ताकि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जन-शक्ति है। समय की माँग है कि गुणात्मकता में सुधार करें तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके।

- >Investments in education convert human beings into human capital; human capital represents enhanced labour productivity, which is an acquired ability and an outcome of deliberate investment decisions with an expectation that it will increase future income sources.
- the-job training, health, migration and information are निर्माण के स्रोत हैं। the sources of human capital formation.
- >शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूँजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूँजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं।
- >Investments in education, on-स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना मानव पूँजी

- The concept of physical capital is the base for conceptualising human capital. There are some similarities as well as dissimilarities between the two forms of capital formation.
- Investment in human capital formation is considered as efficient and growth enhancing.

- भौतिक पूँजी की संकल्पना मानव पूँजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूँजी निर्माण के दोनों प्रकारों में कुछ समानताएँ और कुछ विषमताएँ हैं।
- मानव पूँजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण तथा संवृद्धि बढ़ान वाला माना जाता है।

- >Human development is based on the idea that education and health are integral to human wellbeing because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, will they be able to make other choices which they value.
- The percentage of expenditure on education of the total government expenditure indicates the importance of education in the scheme of things for the government.
- ▶मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं।
- ेकुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है।